(b) Certain clauses of the scheme are being reconsidered in the context of the U. K. laws and policies.

PUBLIC AND ANGLO-INDIAN SCHOOLS

719. SHRI B. C. PATTANAYAK : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India are unable to implement the national educational policy in the schools run by the Inter-State Anglo-Indian Education Board and in the Public Schools;

(b) whether Government propose to ascertain the total amounts of grants received by these schools annually and also in lumpsum from the British High Commission in India, the U.S. Embassy, C.I.A. and the P.L. 480 Fund;

(c) whether the Government of India have entered into any agreement with the British Government regarding these schools; and

(d) the names of the examinations conducted by these schools, the details of the courses prescribed for them and the regular examinations to which these examinations are considered equivalent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) The implementation of National Policy in respect of schools in general is the concern of the State Governments. As far as the schools run by the Inter-State Anglo-Indian Education Board are concerned, it has not been possible to enforce the principles enunciated in the National Policy Resolution in all schools in view of the provisions of Article 30 of the Constitution of India giving a right to all minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

As regards the Public Schools, the Indian Public Schools Headmasters' Conference resolved at their conference held in February, 1969, that every endeavour should be made to make it possible for a wider public to avail itself of education at its schools and that the member schools should take all measures to find ways and means of instituting scholarships on the basis of means and merit basis.

(b) The necessary information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

(c) No, Sir.

(d) The necessary information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as early as possible.

REQUEST FROM BIHAR FOR FINANCIAL ASSISTANCE

720. SHRI BHOLA PRASAD : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar has requested for financial assistance from the Union Government in order to make the system of payment of salaries to the college teachers regularly; and

(b) if so, whether the Central Government are considering their request sympathetically ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b) The State Government of Bihar had requested that the Central assistance for implementation of the U.G.C. pay scales for university and college teachers may be continued beyond 1970-71 upto the end of the current Fourth Five-Year Plan period. The State Government has been informed that it was not possible to make a departure in the case of Bihar alone from the approved terms of the Scheme and provide assistance for a period of 8 years in all, *i.e.* upto 1973-74, as against five years as originally envisaged in the Scheme.

विदेशी ऋण

721. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विदेशों से कितने प्रकार के ऋण ले रखे हैं तथा गत तीन वर्षों में ऐसे ऋणों की कुल राशि कितनी थी;

(ख) इन ऋणों की कितनी राशि को अनुदानों में परिवर्तित कर दिया गया है और कितनी राशि लौटानी होगी तथा लौटाने की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस समय सभी प्रकार के विदेशी ऋणों का प्रति व्यक्ति कितना भार है;

(घ) किन-किन देशों से और किन शर्तों पर ऋण लिया हुआ है; और

(ङ) किन-किन देशों ने भविष्य में ऋण देना स्वीकार किया है और उनको प्राप्त करने तथा लौटाने की शर्तें क्या होंगी?

†[FOREIGN LOANS

721. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the various types of foreign loans received by Government and the total amount of such loans during the last three years;

(b) the amount out of these loans which has been converted into grants and the amount required to be repaid and the terms of repayment:

(c) the *per capita* burden of all types of foreign loans at present;

(d) the names of the countries from which loans have been taken and the terms of these loans; and

(e) the names of the countries which have agreed to extend loans in future and the terms of receipt and repayment of such loans ?]

वित्त मंत्रालय में राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1967-68 से 1969-70 तक के विभिन्न प्रकार के विदेशी ऋण (अनुदानों के रूप में ऋण-परिशोधन संबंधी राहत को छोड़ कर) जिनके लिये विभिन्न देशों द्वारा वचन दिये गये

(करोड़ रुपयों में)

देश/संस्था का नाम	प्रायोजना-भिन्न ऋण	प्रायोजनागत ऋण	जोड़
I. मुक्त विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण			
क. -सहायता संघ के सदस्य--			
1. आस्ट्रिया	4.2	..	4.2
2. बेल्जियम	6.0	7.5	13.5
3. कनाडा	71.0	46.5	117.5
4. डेनमार्क	7.0	..	7.0
5. फ्रांस	30.9	30.4	61.3
6. जर्मनी	103.9	37.1	141.0
7. इटली	9.6	12.0	21.6
8. जापान	106.5	..	106.5
9. नीदरलैण्ड	23.4	..	23.4
10. स्वीडन	..	10.9	10.9
11. ब्रिटेन	166.5	42.3	208.8
12. संयुक्त राज्य अमेरिका	504.1	96.1	600.9

†[ ] English translation.

देश संस्था का नाम	प्रायोजना-भिन्न ऋण	प्रायोजनागत ऋण	जोड़
13. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक . . .	33.8	49.8	82.9
14. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ .	150.0	88.1	238.1
जोड़-क . . .	1216.9	420.7	1637.6
ख-सहायता संघ से भिन्न पश्चिमी यूरोप के देश			
नार्वे . . .	..	1.5	1.5
जोड़-ख . . .	..	1.5	1.5
जोड़ (क+ख) . .	1216.9	422.2	1639.1
II. वस्तुओं के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण			
बुल्गारिया . . .	..	11	11.3
कुल जोड़ (I+II) . .	1216.9	433.5	1650.4

टिप्पणी :—उपर्युक्त सारणी में इन मदों के अन्तर्गत प्राप्त सहायता शामिल नहीं की गई है:—(1) पी० एल० 480 सहायता, (2) 1970-71 के लिए 1969-70 में ब्रिटेन से प्राप्त ऋण-परिशोधन सम्बन्धी सहायता, (3) 4 अप्रैल 1968 का रूमानियन ऋण क्योंकि ऋण-करार में ऋण की रकम निर्दिष्ट नहीं की गयी है।

सामान्यतः ऋणों को अनुदानों में नहीं बदला जाता और ऋणों की वापसी अदायगी निश्चित तारीख को की जाती है। लेकिन पिछले दो वर्षों में, ऋण परिशोधन सम्बन्धी राहत के संदर्भ में, ऋण संबंधी अदायगियों की 9.8 करोड़ रुपये की छोटी सी रकम को अनुदानों में बदला गया था। विभिन्न देशों/संस्थाओं से प्राप्त वर्तमान ऋणों की शर्तें संलग्न अनुबन्ध में दी गयी हैं। **(नीचे देखिए)**

विदेशी ऋणों की बकाया रकमें, कुछ मामलों में 50 वर्षों तक की अवधि में निर्यात से होने वाली आय से और विदेशी प्राप्तियों से चुकायी जाती हैं। इसलिए विदेशी ऋणों के प्रति-कार्य भार की बात करना अर्थपूर्ण नहीं है। पर यदि कुल बकाया रकम से अनुमानित जनसंख्या से भाग दिया जाय तो यह रकम 92.92 लाख रुपये बैठती है।

भारत सहायता संघ के सदस्य प्रत्येक वर्ष के लिए सहायता के वचन देते हैं। जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है, मई, 1970 में हुई संघ की बैठक में संघ के सभी सदस्यों ने अपने-अपने विधान मण्डल की स्वीकृति मिलने तक, सहायता के लिए अनन्तिम रूप से वचन दे दिये थे। कुछ मामलों में 1970-71 के वचनों के आधार पर पहले ही द्विपक्षीय

करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, स्वीडन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ या तो वचन की पूरी रकम के लिए या उसके कुछ अंश के लिए यह सहायता करारों पर हस्ताक्षर किये जाने हैं, उनके ऋणों की वापसी अदायगी की शर्तें मालूम होंगी जब द्विपक्षीय करारों के बारे में बातचीत हो जायेगी और उन पर हस्ताक्षर हो जायेंगे।

अनुबंध

विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाले चालू ऋणों की शर्तें

देश संस्था का नाम	ऋणों की शर्तें		
	रियायती अवधि सहित ऋण की अवधि (वर्ष)	रियायती अवधि (वर्ष)	ब्याज की दर (प्रतिशत)
I. सहायता संघ के सदस्य—			
1. आस्ट्रिया	25	7	3
2. बेल्जियम			
(i) सरकारी ऋण	30	10	2
(ii) सम्भरक ऋण	10	—	6-7
3. कनाडा			
(i) उदार ऋण	50	10	ब्याज मुक्त
(ii) निर्यात ऋण बीमा निगम ऋण	15-20	3-6	6
4. डेनमार्क	25	7	ब्याज मुक्त
5. फ्रांस			
(i) सरकारी ऋण	25	5	3.5
(ii) फ्रांसीसी बैंक ऋण	10	—	7.55
6. पश्चिम जर्मनी	30	8	$2\frac{1}{2}$
7. इटली			
(i) सम्भरक ऋण	10	—	6
(ii) ऋण-परिशोधन सम्बन्धी राहत	12	3	4
8. जापान	18	5	5.25
9. नीदरलैण्ड	30	8	2.5
10. स्वीडन	25	10	2
11. ब्रिटेन	25	7	ब्याज मुक्त
12. संयुक्त राज्य अमेरिका			
(i) निर्यात-आयात बैंक	10-20	3	6
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	40	10	2-3
13. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	30	10	7

14. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ . .	50	10	3/4
II. सहायता संघ से भिन्न पश्चिम यूरोप के देश–			(सेवा प्रभार)
15. स्विट्जरलैण्ड . .	10-15	5-10	3-6
16. नार्वे . . .	25	5	2
III. पूर्वी—समाजवादी जनतंत्र संघ–			
17. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ .	12	—	2.5
18. हंगरी . .	10	—	2.5
19. यूगोस्लाविया . .	11	—	3
20. चेकोस्लोवाकिया . .	8-12	—	$2\frac{1}{2}$
21. पौलैण्ड . . .	8-12	—	$2\frac{1}{2}$
22. बुलगारिया . . .	11	—	2

†[THE MINISTER OF REVENUE AND EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (e). A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Various types of foreign loans (excluding debt relief in the form of grants) committed by the various countries for the last three years i.e. 1967-68 to 1969-70.

(Rs. in crores)

Name of the Country/Institution	Non-Project Loans	Project Loans	Total
I. *Loans repayable in free foreign exchanges*			
A. *Consortium Members*—			
1. Austria	4·2	..	4·2
2. Belgium	6·0	7·5	13·5
3. Canada	71·0	46·5	117·5
4. Denmark	7·0	..	7·0
5. France	30·9	30·4	61·3
6. Germany	103·9	37·1	141·0
7. Italy	9·6	12·0	21·6
8. Japan	106·5	..	106·5
9. Netherlands	23·4	..	23·4
10. Sweden	..	10·9	10·9
11. U. K.	166·5	42·3	208·8
12. U.S.A.	504·1	96·8	600·9
13. I.B.R.D.	33·8	49·1	82·9
14. I.D.A.	150·0	88·1	238·1
TOTAL—A . .	1216.9	420·7	1637·6

†[ ] English translation.

Name of the Country/Institution	Non-Project Loans	Project Loans	Total
B. *Non-Consortium Western Europe—*			
Norway	..	1·5	1·5
TOTAL—B	..	1·5	1·5
TOTAL (A+B)	1216·9	422·2	1639·1
II. *Loans repayable through export of Goods—*			
Bulgaria	..	11·3	11·3
GRAND TOTAL (I+II)	1216·9	433·5	1650·4

NOTES.—The above table excludes (i) PL-480 assistance (ii) U.K Debt Relief Assistance for 1970-71, received during 1969-70, (iii) Rumanian credit of 4-4-1968 since the amount of the credit has not been specified in the loan agreement.

Normally there is no practice to convert loans into grants and the repayments are effected as and when payments fall due. However, during the last two years, in the context of debt relief, a small part of the debt payments amounting to Rs. 9.8 crores was converted into grants. Terms and conditions attached to current loans from various countries/institutions are given in the Annexure. (*See* below)

Outstanding amounts of foreign loans are repayable over a period, extending in some cases to as much as 50 years, out of export earnings and other external receipts. It may not be meaningful, therefore, to talk of per capita burden of foreign loans. If, however, the total amount outstanding is divided by the estimated population, it will come to about Rs. 92.92.

The members of the Aid India Consortium commit aid on annual basis. As regards the current year, all the member countries of the Consortium announced their provisional commitments of aid, subject to approval of their Legislatures, at the May, 1970 Consortium meeting. In some cases the bilateral agreements against commitments for 1970-71 have already been signed. Aid Agreements with Belgium, Canada, Denmark, France, Italy, Japan, Sweden, U.K., USA and IBRD/IDA have yet to be signed either for full amounts or balance of the total commitment. Terms and conditions of current loans are given in the Annexure. The terms of repayments of loans, yet to be signed, will be known when the bilateral credits are negotiated and signed.

ANNEXURE

Terms and Conditions attached to current loans from various countries

Name of Country/Institution	Terms and Conditions of loans		
	Maturity including Graced period (Yrs.)	Grace period (Yrs.)	Rate of Interest (%)
I. *Consortium Members—*			
1. Austria	25	7	3
2. Belgium :			
(*i*) Governmental credits	30	10	2
(*ii* Suppliers Credit	10	..	6-7

Name of Country Institution	Terms and Conditions of loans		
	Maturity including Graced period (Yrs.)	Grace period (Yrs.)	Rate of Interest (%)
3. Canada—			
(*i*) Soft Loans	50	10	No Intt.
(*ii*) ECIC Credits	15—20	3—6	6
4. Denmark	25	7	No Intt.
5. France			
(*i*) Government Credit	25	5	3·5
(*ii*) French Banks Credit	10	..	7·55
6. West Germany	30	8	2½
7. Italy :			
(*i*) Suppliers credit	10	..	6
(*ii*) Debt Relief	12	3	4
8. Japan	18	5	5·25
9. Netherlands	30	8	2·5
10. Sweden	25	10	2
11. U. K.	25	7	No. Intt.
12. USA :			
(*i*) Exim	10—20	3	6
(*ii*) AID	40	10	2—3
13. IBRD	30	10	7
14. IDA	50	10	¾ (Service Charge)
II. *Non-consortium West Euroepean Countries*—			
15. Switzerland	10—15	5—10	3—6
16. Norway	25	5	2
III. *East European Countries*—			
17. USSR	12	..	2·5
18. Hungary	10	—	2·5
19. Yugoslavia	11	..	3
20. Czechoslovakia	8—12	..	2½
21. Poland	8—12	..	2½
22. Bulgaria	11	..	2

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता

722. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अंतरिम सहायता किस-किस विभाग को मिलेगी और किस-किस विभाग को नहीं मिलेगी और क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय दरों पर सहायता दी जायेगी; यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि क्या होगी; और